

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 261 बेमेतरा, सोमवार 18 मई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने अपने सभी 250 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव करोल बाग में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. यहां प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर चढ़कर प्रदर्शन किया. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पेट्रोल पंप और मदर डेयरी बूथ के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इसी बीच झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के पास 108 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति के नजदीक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव बैलगाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन करने पहुंचे. इस दौरान हाथों में तख्तियां, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे. दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जो सरकार महंगाई के खिलाफ चुनाव जीतकर आई थी उसके शासन में आज महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं.

सीबीआई ने महिला प्रोफेसर को किया गिरफ्तार

नईदिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। अब एजेंसी ने महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली जीव विज्ञान की महिला प्रोफेसर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने उक्त महिला को पेपर लीक गिर्रोह का दूसरा सरगना बताया है। सीबीआई ने बताया कि मंधारे को दिल्ली से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। नीट पेपर लीक मामले में ये सीबीआई की 9वीं गिरफ्तारी है। सूत्रों ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि मंधारे ने छात्रों से लाखों रुपये लेकर विशेष कक्षाएं संचालित कीं। इस दौरान लीक हुए प्रश्न, उनके विकल्प और उत्तर छात्रों को बोलकर लिखवाए गए। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से प्रश्न पत्रों के 2 सेट- एक हाथ से लिखा हुआ और एक टाइप किया हुआ - लीक हुए थे। इसके पीछे कल गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और मंधारे का हाथ था।

ओडिशा की भक्त ने शिरडी के साई बाबा को 10 लाख रुपये का सोने का ब्रौच चढ़ाया

शिरडी। दुनिया भर से भक्त अपनी आस्था और भक्ति के लिए लाखों लोग प्रतिवर्ष साई बाबा के मंदिर में आते हैं. हाल ही में, ओडिशा के भुवनेश्वर की एक महिला भक्त ने साई बाबा के चरणों में 10 लाख रुपये कीमत का एक बेहद आकर्षक और नक्काशीदार सोने का ब्रौच चढ़ाया है. ओडिशा के भुवनेश्वर की रहने वाली साई भक्त संजुक्ता स्वेन अपने परिवार के साथ पिछले 17 सालों से साई बाबा के दर्शन के लिए नियमित शिरडी आ रही हैं. वे साल में कम से कम दो बार बाबा की दरगाह पर जरूर जाते हैं. उन्होंने कहा, साई बाबा ने हमें सब कुछ दिया है.

स्वीडन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-लड़ाकू विमानों ने किया एस्कोर्ट

व्यापार,एआई और रक्षा सहयोग पर होगी बड़ी चर्चा-पीएम

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे। इस दौरान उनके विमान को स्वीडन के अत्याधुनिक ग्रिपेन फ़ाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया, जिसे दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा और रणनीतिक सहयोग के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री रॉब येतन ने पीएम मोदी को विदा किया, जबकि स्वीडन पहुंचने पर प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।पीएम नरेन्द्र मोदी का विमान जैसे ही स्वीडन के एयरस्पेस में प्रवेश किया, स्वीडिश वायुसेना के ग्रिपेन लड़ाकू विमानों ने उसे सुरक्षा और औपचारिक एस्कॉर्ट प्रदान किया। इससे

पहले यूएई यात्रा के दौरान भी इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई थी, जहां एफ-16 जेट्स ने भारतीय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया था। प्रधानमंत्री मोदी रविवार और सोमवार को स्वीडन में रहेंगे। यह यात्रा स्वीडिश प्रधानमंत्री के निर्मंत्रण पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक समीक्षा करेंगे और व्यापार, निवेश तथा तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में लगभग 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। दोनों देश अब पर्यावरण-अनुकूल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्टार्टअप, लचीली स्प्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु



परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। उन्होंने बताया कि स्वीडन में रहने वाला भारतीय समुदाय इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है और इससे

लोगों के बीच जुड़ाव और बढ़ेगा। राजदूत के अनुसार, पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान स्वीडिश प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा यूरोपीय और स्वीडिश उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। वे 'यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री' को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोप की

प्रमुख कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2018 में भारत-डुनार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीडन गए थे। यह नया दौरा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भी मौजूद रहेंगी. यह मंच यूरोप के बड़े उद्योग समूहों का प्रमुख व्यापारिक मंच माना जाता है. स्वीडन रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन खुद एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी.

प्रधानमंत्री मोदी बोले- भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को मिलाई नई गति

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी नीदरलैंड यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती मिली है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाते हुए जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, नवाचार, रक्षा, स्थिरता और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भविष्य का महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती और मजबूत होगी. उन्होंने प्रधानमंत्री रॉब जेटन को गर्मजोशी से स्वागत और एयरपोर्ट पर विदाई देने के लिए धन्यवाद भी दिया.

ब्रिटेन की राजनीति में मचा भूचाल

अपने इस्तीफे की तैयारी में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर.....

नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है. स्थानीय चुनावी हार के बाद 70 से ज्यादा लेबर सांसदों और कई मंत्रियों ने कीर स्टारमर से इस्तीफे की मांग की है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि वह पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। डेली मेल की रिपोर्ट में कैबिनेट के एक सदस्य के हवाले से यह दावा किया गया है। लेबर पार्टी में बढ़ते असंतोष, खास जनसमर्थन और आंतरिक दबाव के



बीच स्टारमर जल्द पद छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। स्थानीय चुनावों में करारी हार के बाद उनपर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। यूनाइटेड किंगडम में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पद छोड़ने को तैयार हैं।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पूछे ये 3 बड़े सवाल

अब तक सस्पेंड क्यों नहीं शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान

नई दिल्ली/ एजेंसी

नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच के बीच अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा सियासी रूप ले लिया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस महा-घोटाले को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वीडियो जारी करते हुए उन्होंने देश के 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ हुए इस धोखे पर सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने 2024 और 2026 के नीट



पेपर लीक की समानताओं को दिखाते हुए सिस्टम पर तंज कसा है और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को लेकर का को लेकर का इस्तीफे की मांग को लेकर का अभियान छेड़ दिया है। नीट-यूजी 2026 पेपर लीक से जुड़े मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में

राहुल गांधी ने लिखा, नीट 2024 पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द नहीं हुई। मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। सीबीआई ने जांच बिठाई। एक कमेटी बनी। नीट 2026 का भी पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया। सीबीआई फिर जांच कर रही है। एक और कमेटी बनेगी। मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है- जवाब दो! अपने वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए तीन बड़े सवाल दगे हैं। बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बार-बार इस 'परीक्षा पे चर्चा' पर आप चुप क्यों हैं? बार-बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं?

राज्य सरकार ने छीन ली डीसी शांतनु सिन्हा बिस्वास की वर्दी

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बड़ी कार्रवाई के बाद कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास की सेवा राज्य सरकार ने समाप्त कर दी है। शुक्रवार रात ये कार्रवाई की गई है। शांतनु सिन्हा बिस्वास पर मनी लॉन्ड्रिंग, उगाही और जमीन कब्जाने से जुड़े पपु सोना के आपराधिक सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप हैं। इस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। मामले की जांच के दायरे में अब कोलकाता पुलिस के 12 अन्य पुलिसकर्मी भी आ गए हैं। सूत्रों के अनुसार, शांतनु सिन्हा बिस्वास पहले कोलकाता पुलिस के सिक्योरिटी कंट्रोल डिवीजन में तैनात थे और कालीघाट थाने के प्रभारी भी रह चुके हैं।



इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस दौरान हवाओं की रफ्तार 65-75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इतनी तेज हवाएं

न केवल यातायात को प्रभावित करती हैं, बल्कि कच्चे मकानों और पेड़ों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कई इलाकों में बारिश के साथ-साथ ओले भी गिर

सकते हैं, जिससे किसानों की फसलों और आम जनजीवन को नुकसान पहुंच सकता है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के निवासियों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मौसम विभाग ने यहाँ रात के समय बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान और हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। हालांकि, राहत मिलने के बजाय गर्मी और बढ़ सकती है, जहां पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां के हालात और भी कठिन हैं। बांदा जैसे जिलों में तापमान 44.8 डिग्री तक जा पहुंचा है, जबकि प्रयागराज और झांसी में भी 44 डिग्री के पार पारा दर्ज किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा

चुनाव आयुक्त चयन पैनल में जज की जरूरी नहीं.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है इसमें जज को शामिल करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र ने कहा कि समिति में किसी जज को चयन शामिल करना संसद का फैसला हो सकता है, लेकिन इसे संवैधानिक मजबूरी नहीं माना जा सकता। सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2023 वाला आदेश सिर्फ अंतरिम व्यवस्था थी। कोर्ट ने



खुद कहा था कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक संसद कानून नहीं बना देती। अब संसद कानून बना चुकी है, इसलिए वही व्यवस्था लागू होगी। सरकार ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सिर्फ चयन प्रक्रिया से तय नहीं होती।

आयोग की संवैधानिक स्थिति, तय कार्यकाल, हटाने की सुरक्षा और दूसरे कानूनी प्रावधान उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। 2023 का कानून इन सभी सुरक्षा प्रावधानों को बरकरार रखता है और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता जोड़ता है। अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, जिसमें सरकार की भूमिका के कारण चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई हो। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी।

राष्ट्रपति मुर्मु ने दी मंजूरी

33 से बढ़ाकर 37 हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या

नई दिल्ली/ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 38 हो गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 38) करने का बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार के फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी है। अब देश की सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 38 हो गई है। मोदी सरकार का यह फैसला ने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। कानूनी समुदाय ने इस निर्णय का स्वागत किया है, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज यानी

17 मई की सुबह कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को मंजूरी दे दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म झू पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि- राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 जारी करके सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने की खुशी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) एक्ट, 1956 में और बदलाव किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने के प्रस्ताव को



मंजूरी दी थी। सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार बढ़ रहे मामलों और न्यायिक कार्यभार को देखते हुए जजों की संख्या बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया था है। लंबे समय से इस मांग को कानूनी समुदाय और वरिष्ठ वकीलों द्वारा

उठाया जा रहा था, ताकि मुकदमों को समय से निपटाने में मदद मिल सके। आखिरी बार 2019 में ये संख्या बढ़ाई गई थी जब मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की संख्या 50 तक पहुंचाने की ज़रूरत थी पड़ सकती है।

कानून के जानकारों ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाले मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जजों की संख्या बढ़ाना समय की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान जजों की कार्यक्षमता और मामलों के निपटारे की दर सराहनीय रही है, लेकिन मामलों की भारी संख्या के कारण अतिरिक्त जज जरूरी हो गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का एक हिस्सा इस साल के अंत तक शुरू हो सकता है। उनके मुताबिक नई व्यवस्था में 38 जजों को आसानी से समायोजित किया जा सकेगा और आने वाले सालों में जजों की संख्या 50 तक पहुंचाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है।

पेंडिंग मामलों में आएगी कमी.....

सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार बढ़ते कामकाज और लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए यह कदम जरूरी हो गया था। नए जजों की नियुक्ति से अदालत की कार्यक्षमता बढ़ेगी और सुनवाई में हो रही देरी को कम करने में मदद मिलेगी। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा पहला कानून वर्ष 1956 में बनाया गया था। इसके बाद समय-समय पर न्यायपालिका की बढ़ती जरूरतों के अनुसार जजों की संख्या में बदलाव किया जाता रहा है। इससे पहले वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। अब नए अध्यादेश के बाद सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत करने तथा लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।



संपादकीय

हिमाचल सरकार ने एक जून से शिक्षा संस्थानों में चिट्ठा के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला भी किया है। मगर यह तभी सार्थक होगा, जब अभिभावकों को भी इससे जोड़ा जाएगा। शांतिप्रिय राज्य की छवि वाले हिमाचल प्रदेश में अब युवाओं के बीच नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। नशीले पदार्थों का जाल

न केवल शहरी, बल्कि ग्रामीण इलाकों तक फैल गया है। एक खास तरह का नशीला पदार्थ, जिसे स्थानीय भाषा में चिट्ठा कहा जाता है, उसकी लत युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही है।दरअसल, जम्मू और पंजाब की सीमाओं से सटे होने के कारण हिमाचल में नशीले पदार्थों की तस्करी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। जांच एजंसियों के तमाम दावों के बावजूद

हिमाचल के युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय

नशे के इस तंत्र पर रोक नहीं लग पा रही है। अब प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए सरकारी नौकरी के लिए युवाओं का ‘एंटी चिट्ठा टेस्ट’ अनिवार्य कर दिया है। साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की भी हर वर्ष ऐसी ही जांच कराई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस कदम से युवाओं को नशे से दूर रखने में कुछ हद तक मदद मिल सकती

है।हिमाचल सरकार ने एक जून से शिक्षा संस्थानों में चिट्ठा के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला भी किया है। मगर यह तभी सार्थक होगा, जब अभिभावकों को भी इससे जोड़ा जाएगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और घरेलू कार्यों की व्यस्तता की वजह से माता-पिता अपने बच्चों पर ज्यादा नहीं दे पाते हैं और उन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी की भी कम

ही जानकारी होती है।ऐसे में किशोरों और युवाओं के साथ-साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रख सकें और उन्हें नशे के दलदल में उतारने से रोक सकें। इसके अलावा राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान से जुड़ने वाले अधिकारियों की वार्षिक रपट में भी इस कार्य का उल्लेख करने की बात कही है। यह

वास्तव में एक व्यावहारिक पहल है।इसमें दोराय नहीं कि राज्य सरकार सतही उपायों के बजाय धरातल पर काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसे राज्य में शिक्षित युवाओं को रोजगार देने की दिशा में भी व्यापक स्तर पर कदम उठाने होंगे, क्योंकि नशे का सेवन करने वालों में छात्रों और बेरोजगार युवाओं की तादाद अधिक है।

ममता का किला ढहाने के लिए भजपा की बंगाल विजय में अहम रही संघ की भूमिका

(श्यामलालयादव)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो प्रचंड जीत मिली है, उसमें बीजेपी संगठन के अलावा आरएसएस की भूमिका काफी अहम रही है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं और प्रचारकों का कहना है कि टीएमसी के शासन में उन्हें काम करने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आई थीं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत में वैसे तो कई कारक रहे हैं, लेकिन एक अहम बिंदु आरएसएस का है। बीजेपी के लिए आरएसएस ने पिछले एक दशक में शांत तरीके से जमीन पर उतरकर काम किया। संगठन में विस्तार की पुरजोर कोशिशें कीं। उसी का नतीजा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता तक पहुंच गई। बीजेपी ने बंगाल के इस बार के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा मुखरता के साथ उठाया था लेकिन ऐसा नहीं है, कि ये बीजेपी के लिए कोई नया मुद्दा नहीं बल्कि यहां हिंदू पहचान की राजनीति का इतिहास एक सदी पुराना है। इसके बावजूद आरएसएस और बीजेपी के पूर्ववर्ती संगठन यानी जनसंघ बंगाल में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब नहीं हो पाया।

बंगाल में लंबा रहा है बीजेपी का संघर्ष – साल 1951 के बंगाल चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 9 विधानसभा सीटें जीती थीं, और 12.57 वोट प्रतिशत का वोट भी हासिल किया था लेकिन उसके बाद यहां से जनसंघ का नामोनिशान मिटता चला गया। इसके बाद जनसंघ का स्वरूप बदला और वो भारतीय जनता पार्टी बन गई। यह लंबा सूखा 2014 में तब समाप्त हुआ, जब बीजेपी ने उपचुनाव में अपनी पहली विधानसभा सीट जीती। बीजेपी ने साल 2016 में 3, 2021 में 77 सीटें जीती थीं। वह मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई थी। इस बार के चुनाव में 207 सीटों के साथ प्रचंड जीत के साथ सरकार बना ली। वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारियों ने बताया कि चुनावी लिहाज से निर्णायक मोड़ 2021 के विधानसभा चुनाव में आयास क्योंकि आरएसएस को यह समझ आ गया था कि अब ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी लड़ाई जीती जा सकती है। पिछले दो वर्षों में संघ ने भाजपा के जमीनी स्तर के तंत्र में मौजूद कमियों को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से 2,000 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को जुटाया था।

संघ ने जमीन पर उतारे थे कार्यकर्ता – ये कार्यकर्ता संघ और पार्टी के कैडर से लिए गए थे। इन कार्यकर्ताओं के सभी खर्चों का वहन पार्टी द्वारा किया गया था और उन्हें एक ही लक्ष्य दिया गया था। जमीन स्तर पर गांवों, बस्तियों विशिष्ट समुदायों के बीच काम करने के लिए आरएसएस ने पूरी ताकत झोंकी थी। संघ की भूमिका बीजेपी की राजनीतिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाली सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ बनाने की थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बंगाल में काफी बड़ा झटका लगा था। इसका काफी हद तक कारण ये माना गया था, कि संघ और बीजेपी के बीच किसी भी तरह का समन्वय स्थापित न हो पाया था।। तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्ड ने द ड्रिंडेन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में यह संकेत दिया था कि पार्टी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान के बाद आरएसएस ने कथित तौर पर अपनी सक्रियता जमीन पर काफी कम कर दी थी।

इस बार के चुनाव में बेहतर था समन्वय – आरएसएस की मध्य बंगाल इकाई के एक पदाधिकारी ने इस बार के चुनाव को लेकर कहा, लगातार समन्वय बना रही। बीजेपी कार्यकर्ता राजनीतिक लड़ाई में सबसे आगे थे, हमारे कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को निडर होकर मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बता दें कि राज्य में आरएसएस की संगठनात्मक संरचना उत्तर, मध्य और दक्षिण बंगाल के तीन क्षेत्रों में विभाजित है।

राज्य के बाहर से आए 2,000 कार्यकर्ता बारी-बारी से काम करते थे जिनकी न्यूनतम तैनाती तीन महीने की होती थी। 150 से

अधिक वरिष्ठ नेता, अन्य राज्यों के विधायक और चुनाव प्रबंधन के अनुभवी लोग भी लगभग दो वर्षों तक राज्य में डेरा डाले रहे। इन नेताओं ने विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में कार्य किया और उनकी भूमिका पारंपरिक चुनाव प्रचार से कहीं अधिक व्यापक थी।

भय के बीच कार्यकर्ताओं ने किया काम – एक बीजेपी नेता ने कहा, कई जगहों पर तो हमारे आरएसएस-भाजपा कार्यकर्ता भी डरे हुए थे और कई जगहों पर उन्होंने शिकायत की कि टीएमसी के लोगों ने उन्हें धमकाया है। डर के मारे हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने काम करना भी बंद कर दिया, लेकिन हमने उन्हें समझाया कि चिंता न करें। हमने उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़पों से बचने और घर-घर जाकर संपर्क साधने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जाति, समुदाय, महिला और छात्र समूहों के साथ-साथ शिक्षक और पेशेवर नेटवर्क में तैनात इन कार्यकर्ताओं ने 15-20 लोगों की अनेकों



सभाएं कीं। इनमेंमें बंगाली गौरव, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी और आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले और सांप्रदायिक विभाजन जैसे भावनात्मक मुद्दों पर सावधानीपूर्वक तैयार किए गए चर्चा बिंदु शामिल थे।

सुनील बंसल का डेटा मैनेजमेंट – जमीनी स्तर की ताकत के अलावा, बीजेपी-आरएसएस ने ऐसी नियुक्तियां भी कीं, जिनसे अंततः अच्छे परिणाम मिले। 2016 के चुनावों में भूपेंद्र यादव और कैलाश विजयगौरीय की जोड़ी सत्ता में थी। 2021 तक पार्टी ने अपने संयुक्त महासचिव (संगठन) शिव प्रकाश और राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन को तैनात कर दिया था। शिव प्रकाश ने आरएसएस की तर्ज पर लगभग पांच साल जमीनी स्तर पर काम किया। बंगाल के प्रभारी वर्तमान भाजपा महासचिव सुनील बंसल ने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित मॉडल को और बारीकी से लागू किया। उत्तर प्रदेश के एक नेता ने बंगाल चुनाव में 6 महीने बिताए थे। उन्होंने बताया कि सुनील बंसल और पार्टी द्वारा इस चुनाव में डेटा-आधारित सटीकता के साथ किए गए कार्य की सराहना की।

उन्होंने कहा, डेटा के मामले में रिसर्च इतनी गहरी थी कि अन्य राज्यों से नियुक्त किए गए 294 विधानसभा क्षेत्रों के सभी प्रभारियों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित 20-25 पृष्ठों की एक फ़ोन्डर दी गई थी। इसमें स्थानीय मुद्दे, पिछले कुछ चुनावों का मतदान पैटर्न, क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता, विभिन्न दलों के प्रमुख पदाधिकारियों के विवरण और संपर्क, साथ ही उनकी कमजोरियां और ताकतें जैसी जानकारीयां भी शामिल थीं।

2016 से डेटा तैयार कर रही थी टीम – पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन के नेताओं ने जिस डेटा का इस्तेमाल किया

था। वह 20216 से बीजेपी के लिए काम करने वाली राजनीतिक रणनीति बनाने वाली एक कंपनी ने जुटाया था। कंपनी के डेटा को देख स्थानीय स्तर के नेता भी काफी चौंक गए थे। उत्तर प्रदेश के एक नेता ने कहा, हम विधानसभा क्षेत्रों में सभी आवश्यक आंकड़ों से लैस थे। स्थानीय नेता और कार्यकर्ता अक्सर जमीनी स्तर की जानकारी और अन्य दलों के नेताओं के बारे में हमारे ज्ञान और समझ से आश्चर्यचकित रह जाते थे। सूची में यह भी शामिल था कि हमारे क्षेत्र में टीएमसी के कौन से नेता अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए काम कर सकते हैं और उनसे संपर्क किया जा सकता है।

टीएमसी ने भी दिया मौका – संघ के नेताओं ने कहा कि टीएमसी की वजह से आरएसएस और बीजेपी का विकास हो सकता है। चुनाव के दौरान राज्य भर में तैनात रहे कोलकाता के संघ एक वरिष्ठ प्रचारक ने कहा, अगर टीएमसी सरकार नहीं होती, तो पश्चिम



बंगाल में बीजेपी की जीत संभव नहीं होती। राज्य में हमारा काम टीएमसी के उदय और मजबूती के साथ बढ़ा और ममता बनर्जी के नेतृत्व में उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण नीतियों के कारण राज्य में सांप्रदायिक विभाजन और भी गहरा गया। 2011 से पहले हमारे पास बहुत कम बंगाली प्रचारक थे। ये वैसी ही स्थिति थी, जैसी पंजाब में बीजेपी की है, जहां उसके पास बेहद कम प्रचारक थे। अब हमारे पास बंगाली प्रचारकों की एक लंबी सूची है, जिनमें न केवल पश्चिम बंगाल मूल के लोग हैं, बल्कि बांला भाषी लोग भी शामिल हैं। एक अन्य आरएसएस पदाधिकारी ने कहा, वामपंथी शासन के दौरान सांप्रदायिक आधार पर ध्ववीकरण करना मुश्किल था। टीएमसी के शासनकाल में यह बहुत आसान हो गया। टीएमसी के शासनकाल में संघ के विस्तार की और इशारा करते हुए अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि राज्य भर में आरएसएस की 1,500 से अधिक दैनिक शाखाएं संचालित होती थीं। अगर यदि साप्ताहिक और मासिक सभाओं का जिक्र करें तो ये संख्या और ज्यादा प्रभावशाली भी नजर आएगी।

किसी राज्य में आरएसएस को नहीं हुई बंगाल जैसी दिक्कतें – आरएसएस नेता ने कहा, समय बीतने के साथ हमने महसूस किया कि बंगाली हिंदुओं के बीच टीएमसी और उसके नेतृत्व के प्रति एक प्रकार की नफरत बढ़ रही थी। हमने पाया कि जिन महिलाओं से हम संपर्क कर रहे थे, उनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं ममता बनर्जी के खिलाफ हो गई थीं। आरएसएस के नेताओं ने कहा कि शाखाएं आयोजित करना संघ के लिए काफी मुश्किल हो गया था। इसको लेकर एक पदाधिकारी ने कहा कि शायद और कोई राज्य ऐसा नहीं था, जहां हमारे लिए संघ की शाखा का आयोजन करना काफी मुश्किल था।

पीएम मोदी के राष्ट्रहित के आह्वान में भी राजनीति क्यों?

(ललितगर्ग)

इसी प्रकार ईंधन के उपयोग में संयम भी समय की आवश्यकता है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयातित तेल पर निर्भर है। खाड़ी देशों में युद्ध और अस्थिरता के कारण तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका सीधा प्रभाव पेट्रोल, डीजल, परिवहन, उद्योग और महंगाई पर पड़ता है।

आज पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं ने मानव सभ्यता को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। खाड़ी देशों में लंबे समय से चल रहे संघर्ष और युद्ध की विभीषिका ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरे तक प्रभावित किया है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि, अपूर्वित श्रृंखलाओं का बाधित होना, डॉलर के मुकाबले विभिन्न देशों की मुद्राओं का कमजोर होना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न असंतुलन ने लगभग हर राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। भारत भी इन परिस्थितियों से अछूता नहीं रह सकता। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है और सोने का भी विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन के संयमित उपयोग और सोने की खरीद को सीमित करने का आह्वान केवल एक आर्थिक सलाह नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में किया गया दूरदर्शी चिंतन है। दुर्भाग्य यह है कि मोदी को मितव्ययिता की अपील पर पूरे देश को एकजुट होकर गंभीरता से विचार करना चाहिए था, उस विषय को भी राजनीतिक विवाद का हथियार बना दिया गया। कुछ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की इस अपील को जनता में भय फैलाने वाला कदम बताया, तो कुछ ने इसे सरकार की विफलताओं को छिपाने का प्रयास कहा। जबकि वस्तुतः यह अपील राष्ट्र को भविष्य की संभावित चुनौतियों के प्रति सचेत करने और समय रहते आत्मनुशासन अपनाने का संदेश है। यह राजनीति का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी का प्रश्न है। जब विश्व के

बड़े-बड़े राष्ट्र आर्थिक संकटों से जूझ रहे हों, तब भारत के प्रधानमंत्री यदि नागरिकों को संयम एवं मितव्ययिता का सूत्र देते हैं तो उसे राजनीतिक चरम्ये से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह पहला अवसर नहीं है, जब प्रधानमंत्री ने देश की तरक्की को बनाए रखने की सामूहिक चिन्ता करते हुए मितव्ययिता एवं संयम की अपील की हो।

भारत की संस्कृति मूलतः संयम प्रधान रही है।

भारतीय जीवन-दर्शन में संयम को केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। हमारे ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों ने सदैव आवश्यकता और विलासिता के बीच अंतर करना सिखाया। महावीर, बुद्ध, गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने त्याग और संयम को ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति बताया। भारतीय संस्कृति कहती है कि जितना आवश्यक हो उतना ही उपभोग करो, क्योंकि असीमित उपभोग अंततः संकट को जन्म देता है। यही कारण है कि भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों तक टिकाऊ और संतुलित बनी रही। आज जब पूरी दुनिया उपभोक्तावाद के दुष्परिणाम भुगत रही है, तब भारत की यही संयम आधारित संस्कृति समाधान का मार्ग दिखा सकती है। सोने के प्रति भारतीय समाज का आकर्षण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर गहरा रहा है। विवाह, पारिवारिक उत्सव, धार्मिक परंपराएं और सामाजिक प्रतिष्ठा में सोने का विशेष स्थान है। लेकिन यह भी एक कठोर सत्य है कि भारत का अधिकांश सोना आयातित होता है। हर वर्ष अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार सोने के आयात पर खर्च होता है। यह सोना उत्पादन या औद्योगिक विकास में उपयोग होने के बजाय घरां और लॉकरों में बंद होकर निष्क्रिय पड़ा रहता है। ऐसे समय में जब विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा हो और रुपये की कीमत लगातार गिर रही हो, तब सोने की खरीद में संयम बरतने की अपील आर्थिक दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। यह किसी की

परंपराओं के विरोध में नहीं, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती के पक्ष में उठाया गया कदम है।

इसी प्रकार ईंधन के उपयोग में संयम भी समय की आवश्यकता है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयातित तेल पर निर्भर है। खाड़ी देशों में युद्ध और अस्थिरता



के कारण तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका सीधा प्रभाव पेट्रोल, डीजल, परिवहन, उद्योग और महंगाई पर पड़ता है। यदि नागरिक ईंधन के अनावश्यक उपयोग को सीमित करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, ऊर्जा बचत को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं, तो इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। संयम का अर्थ केवल त्याग नहीं होता, बल्कि दूरदर्शिता और जिम्मेदारी भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील इसी जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित प्रतीत होती है। उन्होंने किसी प्रकार की जबर्दस्ती या प्रतिबंध की बात नहीं की, बल्कि नागरिकों से स्वेच्छक सहयोग की अपेक्षा की। यह लोकतांत्रिक नेतृत्व की पहचान है।

एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री का कर्तव्य केवल संकट आने पर

कदम उठाना नहीं होता, बल्कि संकट के संकेतों को पहचानकर समय रहते जनता को तैयार करना भी होता है। आज जब दुनिया के कई देशों में आर्थिक अस्थिरता के कारण भारी महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव देखने को मिल रहे हैं, तब भारत अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति में है। यह केवल संयोग नहीं,

बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में अपनाई गई आर्थिक नीतियों, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत अभियान और वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत स्थिति का परिणाम है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वव्यापी संकटों के बावजूद भारत ने अपने नागरिकों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया। महामारी से लेकर युद्धजनित परिस्थितियों तक भारत सरकार ने लगातार राहत योजनाएं चलाई, गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, किसानों और मध्यम वर्ग को विभिन्न प्रकार की सहायता दी तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए। वैश्विक मंदी और युद्ध के वातावरण में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बना हुआ है। यह प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रमाण है।

दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि देशहित के ऐसे विषयों पर भी कुछ राजनीतिक दल संकीर्ण राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे। लोकतंत्र में अलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन हर विषय को राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू में तोलना राष्ट्रहित के विरुद्ध है। यदि प्रधानमंत्री जनता से संयम की अपील करते हैं तो विपक्ष को चाहिए कि वह भी जनता को जागरूक करे, न कि भय और भ्रम का वातावरण बनाए। राजनीति तब तक स्वस्थ मानी जाती है जब तक वह राष्ट्रहित से जुड़ी रहे। लेकिन जब राजनीति केवल विरोध के लिए विरोध करने लगे और

राष्ट्रीय संकटों को भी अवसर की तरह देखने लगे, तब वह लोकतंत्र को कमजोर करती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरा देश एक परिवार की तरह सोचते हुए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माने। संकट के समय संयम, अनुशासन और सहयोग ही किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। भारत ने इतिहास में अनेक बार यह सिद्ध किया है कि जब भी राष्ट्र पर संकट आया, भारतीय समाज ने अद्भुत त्याग और एकता का परिचय दिया। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर युद्धकाल तक, भारतीय जनता ने अपने निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को महत्व दिया है। आज फिर वही समय है जब हमें समझना होगा कि अनावश्यक उपभोग, दिखावे की प्रवृत्ति और अधांधुंध विलासिता अंततः देश की आर्थिक मजबूती को कमजोर करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को इसी व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। यह केवल सोना न खरीदने या ईंधन बचाने का संदेश नहीं, बल्कि आत्मसंयम, आत्मअनुशासन और राष्ट्रीय जिम्मेदारी का संदेश है। भारतीय संस्कृति का मूल स्वर भी यही रहा है कि व्यक्ति अपने आचरण से समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाए। यदि हम संयम को जीवन का हिस्सा बना लें तो अनेक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान स्वतः संभव हो सकता है। आज दुनिया जिस अनिश्चितता और संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें जिस अविश्वसनीय मजबूत स्थिति में खड़ा है। इसका श्रेय देश की जनता की साधर्म्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी जाता है। ऐसे समय में आवश्यकता राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सकारात्मक सोच की है। संयम केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण का आधार है। यदि हम इस भावना को समझ सकें, तो न केवल वर्तमान संकटों का सामना कर पाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकेंगे। लेखक, पत्रकार, स्तंभकार है।) (इस लेख में संकट आया, भारतीय समाज ने अद्भुत त्याग और एकता का परिचय दिया। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर युद्धकाल तक, भारतीय जनता ने अपने निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को महत्व दिया है। आज फिर वही समय है जब हमें समझना होगा कि अनावश्यक उपभोग, दिखावे की प्रवृत्ति और अधांधुंध विलासिता अंततः देश की आर्थिक मजबूती को कमजोर करती है।



खेपों को रोकने और वैश्विक शूलक लगाने की धमकी देने के बाद, यह कसम खाई है कि क्यूबा को अब और तेल या पैसा नहीं मिलेगा। इस द्वीप के भविष्य को लेकर चल रही वार्ताओं के बीच, एंप ने कहा, उन्हें क्यूबा को अपने अधिकार में लेने की उम्मीद है। यह बयान उन्होंने जनवरी में वनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल करने के प्रयास के बाद दिया था।



मिचेल मार्श
93 रन
35 गेंद
4 चौके
10 छक्के

कोलकाता ने गुजरात को 29 रन से हराया

सुदर्शन गिल और बटलर की मेहनत पर फिरा पानी

ईडन गार्डन्स । आईपीएल में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हरा दिया। कोलकाता ने ईडन गार्डन्स में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी।

एलन ने 35 गेंदों में 93 रन बनाए

कोलकाता के लिए फिन एलन ने 35 गेंदों में 93 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। वहीं अंककृष रघुवंशी ने नाबाद 82 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 44 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 7 छक्के लगाए। अंतिम ओवरों में कैमरन ग्रीन ने भी 28 गेंदों में नाबाद 52 रन बनाए। उनकी पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। कप्तान अजिंक्य रहाणे 14 रन बनाकर आउट हुए। गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज और साई किशोर को 1-1 विकेट मिला। हालांकि, टीम के ज्यादातर गेंदबाज महंगे साबित हुए। राशिद खान ने 4 ओवर में 57 रन खर्च किए, जबकि अरशद खान के

एकमात्र ओवर में 22 रन आए। केकेआर ने गुजरात को 29 रनों से हरा दिया। शनिवार को खेले गए मुकाबले में केकेआर द्वारा दिए गए 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात चार विकेट पर 218 रन ही बना सकी।

केकेआर ने गुजरात को हराया

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने गुजरात टाइटन्स को 29 रनों से हरा दिया। शनिवार को ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने फिन एलन, अंककृष रघुवंशी और कैमरन ग्रीन की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में दो विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम चार विकेट पर 218 रन ही बना सकी। इस दौरान शुभमन गिल, जोस बटलर और साई सुदर्शन ने अर्धशतक जड़े। वहीं, केकेआर के लिए सुनील नरेन ने दो विकेट लिए जबकि सौरभ और ग्रीन को एक-एक मिला।

गुजरात को तीसरा झटका गुजरात को तीसरा झटका सौरभ दुबे ने दिया। उन्होंने बटलर को अपना शिकार बनाया। वह 57 रन



बनाकर आउट हुए। अब राहुल तेवतिया बल्लेबाजी के लिए आए हैं।

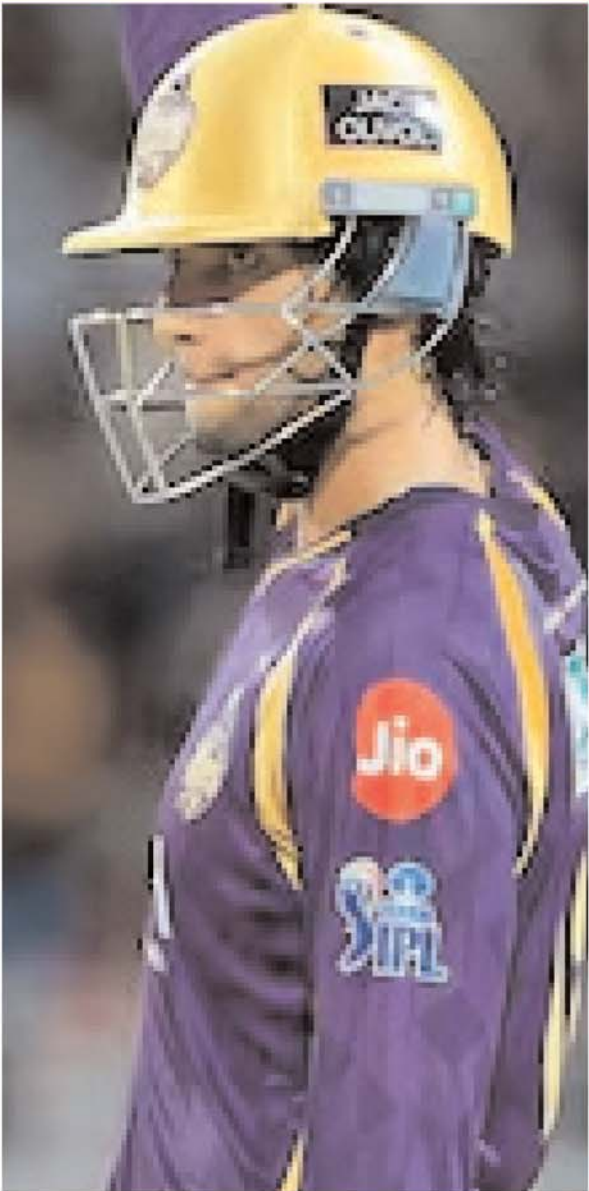
: गुजरात को दूसरा झटका

गुजरात को दूसरा झटका सुनील नरेन ने दिया। उन्होंने अनुकूल रॉय के हाथों शुभमन गिल को कैच कराया। वह 49 गेंदों में 85 रन



बनाकर आउट हुए। अब जोस बटलर का साथ देने साई सुदर्शन आए हैं।

बटलर का अर्धशतक बटलर ने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वह गिल के साथ 71 गेंदों में 128 रनों की साझेदारी निभा चुके हैं।



हसन अली के सिर में चोट, स्ट्रेचर पर बाहर गए

बांग्लादेश के खिलाफ हुई घटना, ठीक होने पर दोबारा गेंदबाजी की

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली को बांग्लादेश के खिलाफ आज से शुरू हुए दूसरे टेस्ट के दौरान सिर पर चोट गई। इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर से मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। हालांकि, पाकिस्तान टीम के लिए राहत की बात यह रही कि वे कुछ समय बाद ही मैदान पर लौट आए और दोबारा गेंदबाजी शुरू कर दी।

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से सिलहट में खेला जा रहा है। बांग्लादेश की पहली पारी 278 रन पर ऑलआउट हो गई है। टीम के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज लिटन दास ने शतक लगाया। उन्होंने 159 गेंदों पर 126 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल रहे।

मैदान पर ऐसे हुआ हादसा



शनिवार को बांग्लादेश के पहली पारी के 8वें ओवर के दौरान जब हसन अली अपनी ही गेंद पर तंजीद हसन तमीम का कैच लपकने के लिए दाईं ओर डाइव लगाए। इस दौरान वे मैदान पर काफी अजीब तरीके से गिरे, जिससे उनके सिर के दाहिने हिस्से पर गंभीर चोट लगी और वे असहज नजर आए। चोट लगने के बाद हसन अली को काफी चक्कर आने जैसी महसूस

हुआ, जिसके तुरंत बाद मेडिकल टीम मैदान पर आई। स्थिति को देखते हुए उन्हें स्ट्रेचर की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया और उनके ओवर की बची हुई गेंदें सलमान आगा ने डालीं।

पाकिस्तान टीम की चिंताएं हुईं दूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम और फैंस के लिए यह चिंता ज्यादा लंबी नहीं रही। हसन अली ठीक होकर मैच के 16वें ओवर की शुरुआत में ही वापस मैदान पर लौट आए। इसके बाद उन्होंने मैच के 19वें ओवर में अपनी गेंदबाजी भी दोबारा शुरू कर दी।

लिटन दास ने 126 रन बनाए लिटन के अलावा बांग्लादेश के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही।

पाकिस्तान की फातिमा की महिला टी-20 में सबसे तेज फिफ्टी

15 गेंदों में जड़ा अर्धशतक; भारत की ऋचा घोष समेत 3 बैटर्स का रिकॉर्ड तोड़ा

कराची। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने महिला टी-20 इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कराची में शुक्रवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी-20 इंटरनेशनल में 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ा।

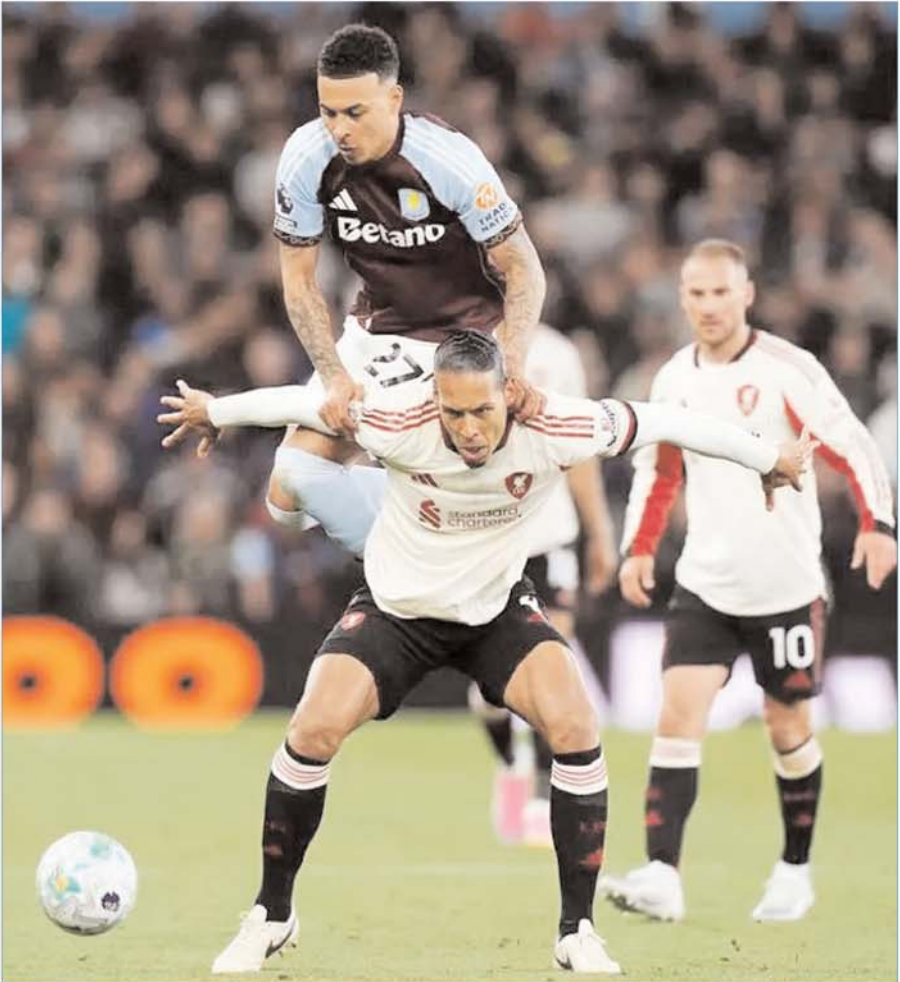
34 साल की फातिमा ने सोफी डिवाइन, फीबी लिचफील्ड और भारत की ऋचा घोष का रिकॉर्ड तोड़ा। इन तीनों ने 18-18 गेंदों में फिफ्टी बनाई थी। इससे पहले पाकिस्तान के लिए यह रिकॉर्ड निदा डार के नाम था। उन्होंने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंदों में फिफ्टी बनाई थी।

विमेंस टी-20 क्रिकेट इतिहास की संयुक्त सबसे तेज फिफ्टी



फातिमा सना की यह पारी इंटरनेशनल के साथ ओवरऑल विमेंस टी-20 क्रिकेट में भी सबसे तेज फिफ्टी है। मैरी केली ने 2022 में बॉव्लिकशायर और लॉरा हैरिस ने 2025 में ओटागो के लिए धरेलू क्रिकेट में 15 गेंदों में अर्धशतक बनाए थे। 19वें ओवर में 24 रन, 19 गेंदों में नाबाद 62 रन तीसरे टी-20 में पाकिस्तान ने टॉस

जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी। फातिमा सना 17वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरीं। तब टीम का स्कोर 152 रन पर 4 विकेट था। उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाया। इसके बाद कुदजई चिगोरा की गेंदों पर लगातार चार चौके जड़े। फातिमा ने 19वें ओवर में नोमवेले सिबांडा के खिलाफ सबसे आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने ओवर में 4, 4, 6, 6 और 4 रन के साथ 24 रन बनाए। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन लेकर अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने पारी का अंत दो चौकों के साथ किया और 19 गेंदों में 62 रन बनाकर नाबाद रहें। इस दौरान 10 चौके और 2 छक्के लगाए।



इंग्लैंड के बर्मिंघम में एस्टन विला और लिवरपूल के बीच हुए इंग्लिश प्रीमियर लीग साँकर मैच के दौरान, लिवरपूल के वर्जिल वैन डाइक (आगे) एस्टन विला के मॉर्गन रोजर्स को गेंद से रोकने की कोशिश करते हुए।

ऋषभ पंत पर लगा 12 लाख का जुर्माना

स्लो ओवर रेट के कारण आईपीएल की कार्रवाई

मुंबई। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत पर आईपीएल गर्बनिंग कार्र्सिल ने 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट के कारण की गई। मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम की इस सीजन में यह पहली गलती थी, इसलिए आईपीएलनियमों के तहत उन पर केवल आर्थिक जुर्माना लगाया गया। ओवर-रेट से जुड़े आर्टिकल 2.22 के अनुसार किसी टीम को तय समय में अपने



20 ओवर डालने होते हैं। ऐसा नहीं होने पर आईपीएल गर्बनिंग कार्र्सिल दोषी पाए जाने पर कप्तान पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। आगे ऐसी गलती दोहराई तो पंत और टीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं आईपीएलनियमों के मुताबिक, अगर लखनऊ की टीम इस सीजन में दोबारा स्लो ओवर रेट की गलती करती है, तो कप्तान ऋषभ पंत पर जुर्माना बढ़कर 24 लाख रुपए हो जाएगा। प्लेइंग इलेवन के बाकी खिलाड़ियों पर भी मैच फीस का 25% या 6 लाख रुपए (जो भी कम हो) का जुर्माना लगाया जाएगा।

मलेशियाई जोड़ी को 82 मिनट में हराया, टूर्नामेंट में तीसरी बार खिताबी मुकाबला खेलेंगे

सात्विक-चिराग थाईलैंड ओपन के फाइनल में

बैंकॉक। बैंकॉक में खेले जा रहे थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी फाइनल में पहुंच गए हैं। दुनिया की चौथे नंबर की भारतीय जोड़ी ने शनिवार को सेमीफाइनल में मलेशिया के गोह स्जे फी और नूर इज्जुद्दीन को 19-21, 22-20, 21-16 से हराया। यह मुकाबला 82 मिनट तक चला।

फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना कल इंडोनेशिया के लियो रोली कानांडो और डेनियल माथिन से दोपहर 12:30 बजे से होगा।

इस सीजन का पहला फाइनल

सात्विक और चिराग ने दबाव में शानदार खेल दिखाया। भारतीय जोड़ी ने दूसरा गेम बेहद करीबी मुकाबले में बचाया और फिर निर्णायक गेम में बढ़त बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। यह इस सीजन में उनकी पहली फाइनल एंट्री है। इससे पहले वे थाईलैंड का 2019 और 2024 टूर्नामेंट का खिताब जीत चुके हैं।

पहला गेम मलेशियाई जोड़ी के

नाम रहा मुकाबले की शुरुआत में मलेशियाई जोड़ी ने फ्रंट कोर्ट पर दबदबा बनाया और 3-1 की बढ़त ले ली। हालांकि सात्विक और चिराग ने तेजी से वापसी करते हुए स्कोर 5-5 कर दिया। पहले गेम में दोनों टीमों के बीच तेज रैलियां और लगातार आक्रामक स्मैश देखने को मिले।

ब्रेक तक मलेशियाई जोड़ी 11-8 से आगे थी। चिराग और इज्जुद्दीन ने कई तेज स्मैश लगाए, जबकि गोह ने नेट के पास शानदार ड्रॉप शॉट खेले। चिराग की कुछ गलतियों की वजह से भारतीय जोड़ी 9-15 से पीछे हो गई। भारतीय खिलाड़ियों ने स्कोर 12-16 तक पहुंचाया, लेकिन इज्जुद्दीन के मजबूत स्मैश और डिफेंस की मदद से मलेशियाई जोड़ी ने 18-12 की बढ़त बना ली। इसके बाद गोह की दो गलतियों और एक लंबी शॉट से भारतीय टीम ने अंतर कम किया, लेकिन अंत में सात्विक नेट पर शॉट मार बैठे और पहला गेम गंवा दिया।

सात्विक-चिराग ने वापसी की



दूसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच काटे की टक्कर रही। स्कोर 3-3 से 6-6 तक बराबरी पर चलता रहा। सात्विक और चिराग ने स्मैश की रफ्तार बदलकर विरोधियों से गलतियां कराई और 9-6 की बढ़त ली। ब्रेक तक भारतीय जोड़ी 11-9 से आगे थी। बाद में गोह ने नेट पर शानदार खेल दिखाते हुए स्कोर 13-13 कर दिया। चिराग के दमदार स्मैश से भारत ने 16-14 की बढ़त बनाई, लेकिन फिर मुकाबला 16-16 पर पहुंच गया। 20-20 पर मैच की सबसे लंबी और तेज रैली देखने को मिली। दोनों जोड़ियों ने लगातार डिफेंस किया। आखिर में इज्जुद्दीन

यूडब्ल्यूडब्ल्यू का बढ़ा फैसला : रूस और बेलारूस के पहलवानों की वापसी

जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संगठन (यूनाइटड वर्ल्ड रेसलिंग) ने बड़ा फैसला लेते हुए रूस और बेलारूस के पहलवानों पर लगी सभी प्रमुख पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया है। अब दोनों देशों के खिलाड़ी तुरंत प्रभाव से सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने राष्ट्रीय झंडे और पहचान के साथ हिस्सा ले सकेंगे। संगठन की ओर से जारी प्रेस विज्ञापि में कहा गया है कि सीनियर स्तर समेत हर श्रेणी की प्रतियोगिता में रूसी और बेलारूसी पहलवान अपने-अपने देश के झंडे के नीचे मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही खिलाड़ियों और टीम स्टाफ को अपनी युनिफॉर्म पर अपने देशों का संक्षिप्त नाम इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी गई है। यदि कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है या टीम चैंपियनशिप अपने नाम करती है, तो पदक समारोह के दौरान संबंधित देश का राष्ट्रगान भी बजाया जाएगा। यूडब्ल्यूडब्ल्यू का यह फैसला पिछले कुछ वर्षों में अपनाई गई सख्त नीति से बिल्कुल अलग माना जा रहा है। वर्ष 2022 में यूक्रेन संघर्ष के बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सिफारिशों के आधार पर रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थीं। उस समय दोनों देशों के पहलवानों और अधिकारियों को यूडब्ल्यूडब्ल्यू के फैलैंडर इवेंट्स में भाग लेने से रोक दिया गया था।



तीसरा गेम 11-5 से जीता

निर्णायक गेम में सात्विक ने ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया। स्कोर 5-5 के बाद भारतीय जोड़ी ने लगातार 6 अंक जीतकर 11-5 की बड़ी बढ़त बना ली। सात्विक के स्मैश और बैककोर्ट शॉट्स ने मलेशियाई खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ा दिया।

मलेशियाई जोड़ी ने वापसी की कोशिश करते हुए स्कोर 13-17 तक पहुंचाया, लेकिन लगातार गलतियों की वजह से वे मैच में वापसी नहीं कर सके। आखिर में सात्विक के क्रॉस-कोर्ट स्मैश से भारत को पांच मैच पॉइंट मिले। एक नेट कॉर्ड के बाद चिराग ने आखिरी शॉट लगाकर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया।



